

सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री रुकने से आमजन हो रहे परेशान, बैंकडेट में पट्टे देने वाले माफियाओं की मौज!

उम्रभर की जमा पूंजी लगाकर सोसायटियों की कॉलोनी में घर खरीदने वाले लोगों के सिर पर तलवार लटकी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राज्य सरकार ने सहकारी सोसायटियों के पट्टों के रजिस्ट्री पर गत मंगलवार से पूर्णतः रोक लगा दी है, इस कारण पिछले 3 दिनों से जहां 600 करोड़ रु. से ज्यादा का राजस्व नुकसान हुआ है। वहीं बैंकडेट में पट्टे काटने काटकर लोगों को ठगने वाली सोसायटियों को अब पट्टा ट्रांसफर के नाम पर मनमानी लूट की खुली छूट भी मिल रही है। वहीं दूसरी ओर उम्रभर की पूंजी लगाकर गैर अनुमोदित (अनअप्रूव्ड) कॉलोनियों में जिन लोगों ने मकान खरीद लिए हैं, उनके सिर पर तलवार लटक गई है। इस मुद्दे को लेकर जहां एक तरफ अधिवक्ता धरना-प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आमजन को रातों की नींद उड़ी हुई है।

आगर राजधानी जयपुर की बात करें तो 17 जून 1999 के बाद सहकारी समितियों का रिकॉर्ड जपूर विकास प्राधिकरण में जमा हुआ ही नहीं। सरकारें बदलती रहीं, परंतु सहकारी समितियों की ऑडिट कभी नहीं हुई। ऐसे में बैंकडेट में पट्टे देने का खेल सोसायटियों ने घडल्ले से खेला। देखा जाएतो पिछले 26 सालों में जयपुर की बसावट पूरी तरह हुई। सहकारी समितियों के पट्टों पर भूखंड बिकते गए और लोगों ने मकान बनाकर रहना भी शुरू कर दिया। परंतु कॉलोनियां काटने वाली सहकारी समितियों ने भी मूल आवंटियों का रिकॉर्ड जेडीए में प्रस्तुत ही

- परंतु अब बिकने वाले भूखंडों के पट्टा ट्रांसफर की आइ में मनमानी रकम लूटेंगी सहकारी सोसायटियां, लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं
- प्रदेश में सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्रियां बंद होने से पिछले 3 दिनों में राज्य सरकार को 600 करोड़ रु. के राजस्व का नुकसान हुआ, अधिवक्ता और आमजन भी सरकार के इस निर्णय के विरोध में उतरे
- प्रदेश में 1999 के बाद सरकारें बदलती रहीं, परतु कोई भी सहकारी समितियों की ऑडिट समय पर नहीं करवा पाया, इस कारण बैंकडेट में पट्टे देने का खेल राजस्थान में खूब पनपा
- सुविधा के नाम पर कॉलोनियों में मात्र सड़कें बनाकर सोसायटियां तो रफुचक्कर हो गईं, अब लोगों के पास दस्तावेज ही नहीं कि, चाहकर भी कॉलोनियों का भू-रूपांतरण (90-ए) करवा सकेें

नहीं किया। दूसरी तरफ राज्य सरकार भी कभी इन कॉलोनियों का नियमन नहीं कर पाई, क्योंकि सोसायटियों ने कॉलोनी काटते समय 70:30 अथवा 60:40 के अनुपात में सुविधा क्षेत्र कहीं छोड़ा ही नहीं।

कॉलोनियां काटकर सहकारी समितियों ने तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, परंतु जो लोग भूखंडों की खरीद-फरोख्त कर रहे थे, उनके पट्टा नाम ट्रांसफर का काम यह समितियां करती

रहीं। कुछ भूखंडधारियों ने अपने प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां करवा ली, परंतु जो लोग आर्थिक असक्षम थे, उनसे 200 से 800 रुपये प्रतिगज के शुल्क पर यह सहकारी समितियां पट्टा ट्रांसफर करती रही। यह पूरा काला कारनामा पिछले 26 सालों से राज्य सरकार की नाक के नीचे चलता रहा, परंतु कोई भी एक्शन नहीं ले पाया।

अब राज्य सरकार ने गत 2 दिसंबर 2025 को सहकारी सोसायटियों के पट्टों और बिना 90-ए

(बिना भू रूपांतरण) वाली कॉलोनियों के पट्टों की रजिस्ट्रियां बंद कर दी तो लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि, सहकारी समितियों पर शिकंजा कसने के बजाय राज्य सरकार का यह फैसला आमजन के सिर पर तलवार लटका रहा है। पिछले 26 सालों में जयपुर समेत पूरे राजस्थान में 70-80 फीसदी बसावट सहकारी समितियों की कॉलोनियों में हुई है, अब सरकार आमजन की परेशानी को समझ बिना ही सोधे रजिस्ट्रियां बंद कर रही है, यह अन्याय है। अब इन कॉलोनियों में भूखंड खरीदने वाले लोगों को मजबूरन सहकारी समितियों के पास जाकर पट्टा ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, जो अपनी मनमानी रकम वसूलेंगे।

दूसरी ओर जहां तक बात, कॉलोनियों के भू-रूपांतरण करवाने की है तो अधिकांशतः कॉलोनियों में निवासरत लोगों को तो यह भी मालूम नहीं है कि कौनसी जगह भूखंड सुविधा क्षेत्र का है और कौनसा नहीं। क्योंकि सोसायटियों द्वारा बसाई गई कॉलोनियों में सुविधा क्षेत्र के नाम पर 20 से 30 फीट चौड़ी सड़कें ही है, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं। अगर किसी कॉलोनी के लोग चाहकर भी भू-रूपांतरण की कार्यवाही करवाना चाहें तो किसी के पास मूल दस्तावेज ही नहीं। सोसायटियों के जिन पदाधिकारियों ने अपना रिकॉर्ड पिछले 26 साल में राज्य सरकार को नहीं दिया, वह आमजन को कैसे दे देंगे?

कांग्रेस नेता गिरिराज खंडेलवाल ने कहा कि, राज्य सरकार द्वारा अचानक सोसायटियों के भूखंडों की रजिस्ट्रियां बंद करना अन्याय है। सरकार का यह फैसला अवैध प्लॉटिंग को वैधता प्रदान करने, भ्रष्टाचार को ढाल देने और आमजन को कानूनी दलदल में धकेलने वाला है। यह साफ दिखाता है कि “जनता ठगी जाएगी और माफिया बचेगा।”

खंडेलवाल ने बताया कि, पिछले 26 वर्षों से राजस्थान में 70-80 प्रतिशत सोसाइटी कॉलोनियों में अवैध प्लॉटिंग, गलत भू-रूपांतरण, बैंकडेट पट्टे, फर्जी रजिस्ट्रेशन और करोड़ों की घूसखोरी का खेल चलता रहा है। राजस्थान में सरकारें बदलती रहीं, परंतु कोई भी इन सोसायटियों पर शिकंजा नहीं कस पाया। अब राज्य सरकार ने भले ही रजिस्ट्री बंद करने का निर्णय ले लिया है, परंतु इससे गलत प्लॉटिंग करने वाली सोसायटियों के पदाधिकारी बच जाएंगे और इसकी सजा आम जनता भुगतेंगी। पिछले 26 साल में राज्य सरकार सहकारी समितियों पर शिकंजा कसने में फेल रही तो अब इसकी सजा आमजन क्यों भुगते? अगर समय पर इन सोसायटियों की ऑडिट होती तो कभी बैंकडेट में पट्टे देने का खेल पनपता ही नहीं।

वर्तमान में सैकड़ों सोसायटियां अवसयन/डिफेक्ट घोषित होने के बावजूद बैंक डेट में पट्टे जारी कर रही है और इसकी आड़ में करोड़ों

रुपये लूट रही है। कई सोसाइटियों पर प्रशासक नियुक्त होने के बावजूद अवैध पट्टों का खेल जारी है, और सरकार के नए नियमों ने इन माफियाओं को और अधिक खुला मैदान दे दिया है। सरकार ने असली दौषियों को बचाने के लिए नियम ऐसे तैयार किए हैं कि सोसाइटी संचालकों पर सख्त कार्रवाई संभव ही न हो, लेकिन खरीददारों पर पूरा बोझ डाल दिया जाए।

उन्होंने कहा कि यह फैसला आम नागरिकों की वर्षों की जमा-पूंजी को संकट में डालने वाला है। लाखों परिवार, जिन्होंने सोसाइटी पट्टों पर प्लॉट खरीदे, अब कानूनी अनिश्चितता में फंस गए हैं। रजिस्ट्रियां बंद होने से लोग अपनी संपत्ति न बच सकेंगे, न गिरवी रख सकेंगे, न निर्माण करा सकेंगे, और न ही बैंक लोन प्राप्त कर सकेंगे।

खंडेलवाल ने कहा कि लैंड कन्वर्जन के नाम पर सरकार हर खरीदार को मजबूर करके 90-ए की जटिल और महंगी प्रक्रिया में धकेल रही है, जबकि असली दोषी सोसाइटी संचालकों पर न कोई दंड है, न जवाबदेही। उन्होंने सरकार से मांग की कि राज्य की सभी सोसाइटियों का स्वतंत्र और फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, अवैध प्लॉटिंग करने वाले सोसाइटी संचालकों पर एफआईआर दर्ज की जाए। 90-ए की प्रक्रिया को जनहित में सरल, सुलभ और सस्ती बनाया जाए।

एस.ओ.जी. ने फर्जी डिग्री उपलब्ध करवाने वाले मास्टरमाइंड को दबोचा

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए फर्जी डिग्री उपलब्ध करवाने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अस्थर्थी बैठाने और वर्तमान में कार्यरत वाले मुख्य अभियुक्त बलराम मीणा को फर्जी बीएससी डिग्री उपलब्ध करवाने वाले मास्टरमाइंड मांगीलाल मीणा निवासी शेरागढ़ जिला कोटा को गिरफ्तार किया किया गया है।

एडीजी बंसल ने बताया कि यह फर्जीवाड़ा तब उजागर हुआ जब प्रमुख शासन सचिव (कार्मिक) के निर्देश पर जिला बूंदी में गठित आंतरिक कमटी ने विगत पांच वर्षों के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की। इस जांच में रोल नंबर 3269761 के अभ्यर्थी बलराम मीणा के आवेदन पत्र पर लगे फोटो और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी के फोटो,हस्ताक्षर में स्पष्ट असमानता पाई गई। संदेह गहरा होने पर रिपोर्ट एसओजी मुख्यालय को भेजी गई। जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया।

एसओजी द्वारा गहनता से किए गए अनुसंधान में पहले यह सामने आया था कि आरोपी बलराम मीणा जिसने डमी बैठानेकर पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में सरकारी नौकरी हासिल की थी। उसके स्थान पर उमेश कुमार



आरोपी मांगीलाल मीणा

चौधरी ने परीक्षा दी थी। साथ ही यह भी पता चला कि उमेश चौधरी से आरोपी बलराम मीणा का संपर्क करवाने में मनफूल सिंह धायल एक प्रमुख माध्यम बना था। जिसने बलराम को डमी उपलब्ध करवाया था। इस खुलासे पर एसओजी द्वारा पूर्व में ही आरोपी मनफूल सिंह धायल और उमेश चौधरी को 3 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मुख्य आरोपी बलराम मीणा 24 सितम्बर 2025 को गिरफ्तार हुआ था।

अग्रिम अनुसंधान में यह पता चला कि बलराम ने डॉक्यूमेंट रेपरिफिकेशन के समय जो डिग्री पेश की थी। वह भी कूटरचित थी। बलराम से सख्ती से पूछताछ के बाद यह जानकारी मिली कि आरोपी मांगीलाल मीणा ने उसे यह फर्जी मार्कशीट और डिग्री उपलब्ध कराई थी। अनुसंधान में

- आरोपी मांगीलाल मीणा ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठानेक नौकरी हासिल करने वाले मुख्य अभियुक्त बलराम मीणा को फर्जी बीएससी डिग्री उपलब्ध करवाई थी

मोनाड यूनिवर्सिटी, हापुड से प्राप्त आधिकारिक पत्रावली में सत्र 2012-15 के विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में बलराम मीणा का नाम अनुपस्थित मिला। जिससे उसकी प्रस्तुत बीएससी (बायो साइंस) की डिग्री और मार्कशीट पूर्णतः कूटरचित सिद्ध हुई।

एसओजी ने गहन प्रयास कर आरोपी मांगीलाल मीणा को गिरफ्तार किया है और अब उससे पूछताछ में यह पता लगाने का कार्य करेगी कि उसने इस फर्जी डिग्री उपलब्ध कराने के कारोबार में और कितने लोगों को शामिल किया है तथा कितने अन्य लोगों को फर्जी डिग्री बेची है। एडीजी बंसल ने दोहराया कि भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी कर सरकारी सेवाओं में प्रवेश पाने की हर कोशिश पर एसओजी की कार्रवाई सख्त,तेज और लगातार जारी रहेगी।

विधानसभा वाहन का फर्जी स्टीकर लगी थार गाड़ी जब्त

जयपुर । शिप्रापथ थाना पुलिस ने ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थार पर लगे फर्जी विधानसभा वाहन प्रवेश का फर्जी स्टीकर लगी गाड़ी को जब्त किया है।पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक के खिलाफ विधानसभा का फर्जी वाहन प्रवेश का स्टीकर लगाने का मामला दर्ज कर थार गाड़ी जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी लोगों पर रौब जमाने व टोल टैक्स बचाने के लिए फर्जी स्टीकर लगा कर रखता था।

पुलिस आयुक्त दक्षिण राजर्षिराज ने बताया कि थाना इलाके में स्थित अरावली मार्ग, आवाहन मंडल की खाली पड़ी भूमि पर पुलिस को गश्त के दौरान एक काले शीशे की थार गाड़ी खड़ी नजर आई। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच-पड़ताल की तो उस गाड़ी पर एमएलए वाहन प्रवेश पत्र का स्टीकर लगा मिला।

थार मालिक देव प्रताप सिंह (32) निलेंद्र सिंह,पटेल मार्ग मानसरोवर निवासी से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि लोगों में अपना रौब और टोल टैक्स बचाने के लिए उसने विधानसभा वाहन प्रवेश का फर्जी स्टीकर लगा रखा है। पुलिस ने थार जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। ये स्टीकर आरोपी ने कहा से बनवाया पुलिस इसके बारे में गहनता से पूछताछ करने में जुटी है।

एवियन बोटूलिज़्म और एवियन इंफ्लुएंजा रोग प्रबंधन पर प्रशिक्षण



पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया।

जयपुर (कासं)। पशुपालन विभाग, वन विभाग, सांभर लेक मैनेजमेंट एजेंसी, वर्ल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में एवियन बोटुलिज़्म तथा एवियन इन्फ्लुएंजा रोग प्रबंधन, बचाव और चिकित्सा पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन आज हुआ। पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा व सांभर लेक मैनेजमेंट एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिबु जाँय की पहल पर राज्य में पहली बार इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जयपुर के आगरा रोड, जामडोली में स्थित पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के रामसर वेटलैण्ड क्षेत्र के पशु चिकित्सकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य एवियन बोटुलिज़्म तथा एवियन इन्फ्लुएंजा रोगों की पहचान, बचाव, समय पर किए जाने वाले उपचार तथा आपदा प्रबंधन के व्यावहारिक ज्ञान को मजबूत करना था।

दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर पशुपालन, गोपालन एवं मत्स्य शासन सचिव डॉ। अमीषा को 12वीं कक्षा का पेपर दिलाने कामों ले जा रहा था, तब राहुल और रामवीर ने उसकी पत्नी के साथ गंदे अपशब्दों का प्रयोग कर छेड़छाड़ की।

पशुओं में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक जानकारी, सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया ही समाधान का आधार है। उन्होंने कहा कि एवियन बोटुलिज़्म और एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे रोग न केवल पशुधन के लिए खतरा है, बल्कि इनके फैलने से व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी होते हैं। इसलिए हर स्तर पर समयबद्ध कार्रवाई, निगरानी और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि विभाग आधुनिक तकनीकों, डिजिटल रिपोटिंग, वैज्ञानिक अनुसंधान और फील्ड प्रबंधन को एकूत कर पशुधन सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। डॉ. शर्मा ने विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया टीमों, लैब नेटवर्क और फील्ड स्टाफ की भूमिका की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कलखीय कार्य किया है और इसी गति को आगे बढ़ाना होगा। शासन सचिव ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। समापन अवसर पर निदेशक डॉ। सुरेशचंद्र मीना, अतिरिक्त निदेशक डॉ।रमेश पंत, संयुक्त निदेशक डॉ।तंषण माथुर, डॉ। संगीता माथुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जानलेवा हमला करने वाला बदमाश 7 साल बाद गिरफ्तार

जयपुर । स्टेट क्राइम ब्रांच पुलिस मुख्यालय की टीम ने करीब सात साल से फरार चल रहे एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल गुर्जर निवासी कामां जिला डींग घातक हथियारों से जानलेवा हमला करने के एक गंभीर मामले में वांछित था। आरोपी की गिरफ्तारी पर दस हजार रुपये का इनाम घोषित है।

यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध हवा सिंह घुमरिया के निर्देशन और अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक राजेश मलिक के निकट सुपरविजन में की गई। टीम को सूचना मिली कि आरोपी राहुल गुर्जर, जो डींग के अडावली गाँव में फरारी काट रहा था। वह उत्तर प्रदेश के कोसी छाता क्षेत्र में आयोजित हो रहे गुर्जरों के मेले में शरीक होने के लिए बस से जा रहा है। इस सूचना पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कामां बस स्टैंड पर घेराबंदी की और आरोपी को डिटेन कर लिया। जिसे बाद में अग्रिम कार्रवाई के लिए

थाना कामां पुलिस को सौंप दिया गया। घुमरिया ने बताया कि घातक हथियारों से हमला और लूट गिरफ्तार आरोपी राहुल गुर्जर 13 मार्च, 2019 को घटित अपराध में फरार चल रहा था। प्रार्थी रवि ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि जब वह अपनी पत्नी अमीषा को 12वीं कक्षा का पेपर दिलाने कामां ले जा रहा था, तब राहुल और रामवीर ने उसकी पत्नी के साथ गंदे अपशब्दों का प्रयोग कर छेड़छाड़ की।

प्रदेश के बड़े अस्पतालों में जयपुरिया अस्पताल की तर्ज पर होगा “क्यू मैनेजमेंट सिस्टम” और “हैल्प डेस्क” व्यवस्था

जयपुर (कासं)। प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में रोगियों को सुगम, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जयपुरिया अस्पताल की तर्ज पर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एवं हैल्प डेस्क व्यवस्था शुरू की जाएगी, ताकि रोगियों को कतारों से मुक्ति मिले और उन्हें इलाज के लिए एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर चक्कर नहीं काटने पड़े। उनकी सहायता का गहन अस्पतालों में एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाएगा, जो पूरी संवेदनशीलता के साथ रोगियों की मदद करेगा।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शुक्रवार को जयपुरिया अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जयपुरिया अस्पताल के निरीक्षण के दौरान क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एवं हैल्प डेस्क व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया और पूरी प्रक्रिया को जानकारी ली। उन्होंने इन दोनों नवाचारों के लिए प्रसन्नता व्यक्त की और अन्य अस्पतालों में भी यह



प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव गायत्री राठौड़ ने जयपुरिया अस्पताल का निरीक्षण किया।

मैकेनिज्म अपनाने पर बल दिया।

राठौड़ ने जयपुरिया अस्पताल में सुविधाओं के विकास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी बड़े अस्पताल ने शैनाल क्वालिटी एश्यरेंस स्टेंडर्ड को पूरा करें और एनक्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करें। बड़े

अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं के उच्चतम मानकों को पूरा करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने अस्पताल परिसर में रोगियों एवं प्रजिनजों के फीडबैक के लिए सुझाव पेटिका स्थापित करने तथा क्यूआर कोड सिस्टम लागू करने के भी निर्देश दिए।

- साफ-सफाई एवं रोगी केन्द्रित नवाचारों पर व्यक्त की प्रसन्नता

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अस्पताल में न्यूरो एवं कार्डियक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि सवाई मानसिंह अस्पताल में रोगी भार कम हो।

उन्होंने इसके लिए जरूरी मानव संसाधन का प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में आपातकालीन इकाई एवं ट्रोपा सेंटर के विकास एवं वहां उपलब्ध सुविधाओं पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने अस्पताल में ओपीडी, इनडोर, ब्लड बैंक, आपातकालीन इकाई, दवा काउंटर, जांच लैब सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में साफ-सफाई एवं रोगी केन्द्रित सेवाओं के

समित शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में तेजी से बदलते जैविक ज़ांखिमों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण

में फीडबैक लिया। रोगियों ने कहा कि अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट व्यवस्था प्रारंभ होने से अब उन्हें कतारों में खड़ा नहीं रहना पड़ता। साथ ही, पारदर्शी तरीके से उपचार मिलता है। एक रोगी ने कहा कि जयपुरिया अस्पताल में साफ-सफाई एवं अन्य सुविधाएं निजी अस्पतालों की तरह मिल रही हैं।

अस्पताल के अधीक्षक डॉ. महेश मंगल ने क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एवं हैल्प डेस्क व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में हर प्रमुख विभाग एवं स्थान पर हैल्प डेस्क स्थापित की जा रही है, ताकि रोगी को संबंधित विभाग में उपचार, जांच एवं दवा आदि प्राप्त करने की जानकारी एवं जरूरी सहायता वहां मिल सके। रोगी को अनावश्यक रूप से अस्पताल में भटकना नहीं पड़े।

ये हैल्प डेस्क काउंटर जनसहयोग के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

आरयूएचएस में दूर होगी मानव संसाधन की कमी

जयपुर । रोगियों को बेहतर रीतिरत चिकित्सा सुविधाएं सुगमता एवं सुलभता के साथ उपलब्ध करवाने तथा सवाई मानसिंह अस्पताल का मरीज भार कम करने के लिए आरयूएचएस अस्पताल में मानव संसाधन की कमी दूर की जाएगी। सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के विस्तार की दिशा में कार्डियो, न्यूरो, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के लिए डेडीकेटेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जल्द प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही, यहां उपलब्ध

इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि रोगियों को शहर में उपचार के लिए एक और बेहतर विकल्प मिले। चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शुक्रवार को आरयूएचएस अस्पताल के निरीक्षण के उपरांत उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में आउटडोर एवं इनडोर में रोगियों की संख्या बढ़ाने तथा उपलब्ध सुविधाओं का पूरा उपयोग करने के लिए एक्शन प्लान जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में निर्धारित

ड्यूटी के अनुसार चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ पूरे समय उपस्थित रहें। उन्होंने इसके लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए।

राठौड़ ने कहा कि अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यकतानुसार सीनियर रेजीडेंट की सेवाएं ली जाएं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में कक्षाओं के नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसे चिकित्सा शिक्षा की दिशा में एक उच्च स्तरीय संस्थान के रूप में विकसित कर रही है, इसलिए यहाँ शोध, अनुसंधान एवं शिक्षण कार्यों का स्तर और बेहतर बनाया जाए।

इससे पहले प्रमुख शासन सचिव ने अस्पताल परिसर में जांच, दवा एवं उपचार व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने आउटडोर, आपातकालीन इकाई, आईसीयू एवं सामान्य वार्ड सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया।